



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051]  
No. 1051]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जुलाई 9, 2009/आषाढ़ 18, 1931  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2009/ASADHA 18, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2009

सं. 79/2009-सीमा शुल्क (न. टै.)

का.आ. 1679(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एशिया-प्रशांत व्यापार करार (पूर्व में जिसे बैंकाक करार के नाम से जाना जाता था) नियमावली, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है यथा :—

उक्त नियमावली में :—

(क) नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा :—

“नियम 8, उद्भव-प्रमाणपत्र-अनुबंध ख में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वरीयता रियायत के लिये पात्र उत्पादों के समर्थन में ऐसा उद्भव-प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा जो अनुबंध क में विनिर्दिष्ट फार्म में हो और निर्यात करने वाले भागीदार राज्य की सरकार द्वारा पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो और अन्य भागीदार राज्यों को अधिसूचित किया गया हो।”

(ख) अनुबंध क के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“अनुबंध-ख

एशिया-प्रशांत व्यापार करार के अंतर्गत वरीयता परक दावे और माल के उद्भव संबंधी प्रमाण-पत्र से संबंधित प्रक्रिया

एशिया-प्रशांत व्यापार करार (एतस्मिन् पश्चात् जिसे “एपटा” से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा :—

1. जारी करने वाले प्राधिकारी.—निर्यात करने वाले एपटा भागीदार राज्य की सरकार द्वारा पदनामित प्राधिकारी या प्राधिकारियों के द्वारा (जिसे बाद में जारीकर्ता प्राधिकारी) उद्भव-प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।

2. उद्भव-प्रमाण-पत्र.—(1) उद्भव-प्रमाण-पत्र :

(क) आई एस ओ ए-4 आकार वाले पेपर में होंगे और अनुबंध क में निर्धारित नमूना पाठ के अनुरूप होंगे, जो अंग्रेजी में मुद्रित होंगे।

(ख) पर एक विशेष संदर्भ संख्या लिखी होगी जो जारी करने वाले कार्यालय के प्रत्येक स्थान के द्वारा अलग-अलग दी गई होगी।

(ग) निर्यात करने वाले एपटा भागीदार राज्य द्वारा निर्यात के समय अथवा “शिपमेण्ट” की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर हाथ से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जायेगा।

(घ) जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष एक के लिये वैध रहेगा।

(ड) बिना किसी विलोपन अथवा अध्यारोपण के होगा, और खाली स्थान पर काटा का निशान होगा ताकि यहाँ बाद में कोई बात जोड़ी न जा सके।

(च) में बाक्स 8 में संगत नियम उल्लिखित होंगे और क्षेत्रीय विषय-वस्तु की प्रयोज्य प्रतिशतता भी दी गई होगी।

(2) उद्भव-प्रमाण-पत्र के चोरी हो जाने, खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में मूल प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि, जो जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी की गई होगी, जिसके बाक्स 3 में "अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" लिखा होगा और मूल उद्भव-प्रमाण-पत्र के जारी होने की तारीख लिखी होगी, स्वीकार की जायेगी और उद्भव-प्रमाण-पत्र की यह अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मूल उद्भव-प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि के भीतर ही जारी की जा सकेगी।

3. उद्भव-प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना:—(i) वरीयतापरक संव्यवहार के लिये संबंधित उत्पादों की आयात प्रविष्टि को दर्ज किये जाने के समय सीमा-शुल्क-प्राधिकारी के समक्ष मूल उद्भव-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) उद्भव-प्रमाण-पत्र को सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष पत्तन पर या आयात स्थान पर वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) जहाँ उद्भव-प्रमाण-पत्र को वैधता अवधि के समाप्त होने के पश्चात् पत्तन या आयात स्थान पर सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भी उस स्थिति में इस प्रमाणपत्र को स्वीकार करना होगा जिसमें अपरिहार्य घटना अथवा अन्य ऐसी किसी कारण से जो नियंत्रणकर्ता के नियंत्रण से बाहर है, के कारण समय सीमा का अनुपालन नहीं हो पाता है।

(iv) संबंधित सक्षम प्राधिकारी सभी मामलों में उद्भव-प्रमाण-पत्र को स्वीकार करेगा बशर्ते कि उत्पाद का आयात उद्भव-प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति के पहले किया गया हो।

(v) जहाँ उत्पाद के उद्भव के बारे में कोई संदेह नहीं है तो उद्भव-प्रमाण-पत्र में दिये गये विवरण में और उत्पादों की आयात संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पत्तन या आयात के स्थान पर दिये गये दस्तावेज में दिये गये विवरण में कोई विसंगति पाई भी जाती है तो इससे उद्भव-प्रमाण-पत्र तथ्यतः अवैध नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें दिये गये तथ्य उक्त उत्पाद के बारे में सत्य हों।

4. सीधे परिवहन का समर्थन करने वाले दस्तावेज.—उक्त नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (ख) के अंतर्गत जहाँ माल का परिवहन एपटा भागीदार राज्यों के भू-क्षेत्र के बाहर किया जा रहा हो, आयात वाले पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, यथा :—

(क) निर्यात करने वाले एपटा भागीदार राज्य में जारी किया गया ग्रे बिल आफ लेडिंग;

(ख) निर्यात करने वाले एपटा भागीदार राज्य के जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी उद्भव-प्रमाण-पत्र;

(ग) माल से संबंधित मूल वाणिज्यिक बीजक; और

(घ) ऐसे समर्थनकारी दस्तावेज जिनसे यह सिद्ध हो कि उक्त नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (ख) का अनुपालन किया गया है।

5. उद्भव का स्थापन.—(i) सीमा शुल्क प्राधिकारी को जब प्रश्नगत माल के दस्तावेजों की सत्यता के बारे में अथवा इसके उद्भव स्तर की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त संदेह होता हो तो वह भूतलभी प्रभाव से यदुच्छिन्न जांच के लिये निर्यात करने वाले एपटा भागीदार राज्य के जारी करने वाले प्राधिकारी से अनुरोध कर सकता है।

(ii) ऐसे अनुरोध के साथ संबंधित उद्भव-प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा और ऐसे कारणों को विनिर्दिष्ट करना होगा तथा अतिरिक्त अन्य जानकारी देनी होगी जिनसे यह पता चले की उक्त उद्भव-प्रमाण-पत्र गलत हो सकता है।

(iii) सत्यापन के परिणाम के आने तक सीमा शुल्क प्राधिकारी वरीयतापरक संव्यवहार को स्थगित रख सकता है :

बशर्ते कि यह किन्हीं प्रशासनिक उपायों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक समझे, आयातकर्ता को माल जारी कर सकता है :

बशर्ते यह भी कि माल पर आयात संबंधी मनाही या प्रतिबंध लागू न हो और इसमें धोखाधड़ी का कोई संदेह न हो।

(iv) (क) जारी करने वाला प्राधिकारी सत्यापन के लिए अनुरोध प्राप्त करने पर शीघ्र ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और अनुरोध के प्राप्ति से तीन महीने के भीतर इसका उत्तर देगा।

(ख) सत्यापन की प्रक्रिया, जिसमें वास्तविक प्रक्रिया के साथ-साथ यह निर्धारण कार्य भी शामिल है कि क्या विषयगत माल का उद्भव हो रहा है या नहीं 6 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए और जारी करने वाले प्राधिकारी को इसके परिणाम के बारे में सूचित कर दिया जाना चाहिए।

(ग) सत्यापन की प्रक्रिया को करते समय उप-पैराग्राफ (iii) के प्रावधान लागू होंगे।

(v) उन मामलों में जिनमें भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारी अनुरोध करने के चार महीने के भीतर कोई उत्तर नहीं पाता है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी वरीयतापरक संव्यवहार के दावे को निरस्त कर सकता है और यदि उत्तर में दी गई जानकारी इतनी पर्याप्त नहीं है कि उससे दस्तावेजों की सत्यता या माल के उद्भव का अभिपुष्टीकरण हो सके तो संबंधित प्राधिकारी द्विपक्षीय परामर्श करके तीन महीने के भीतर इस विवाद का समाधान खोजेगा, जिसके न हो पाने पर वरीयतापरक संव्यवहार से इन्कार किया जा सकता है।

6. गन्तव्य स्थान में परिवर्तन.—यदि किसी विशेष पत्तन को निर्यात किये जाने वाले उत्पाद के पूरे भाग या उसके कुछ

भाग के गन्तव्य स्थान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो, उसके भारत में पहुंचने पर या पहुंचने के बाद, निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा, यथा :—

(क) यदि उत्पाद को भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है तो उद्भव-प्रमाण-पत्र, आयातकर्ता द्वारा लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर, में यह पृष्ठांकित करना होगा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण उत्पाद या उसका भाग और मूल प्रमाण पत्र आयातकर्ता को लौटा दिया गया है।

(ख) जैसा कि उद्भव-प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है यदि भारत के लिए परिवहन के दौरान गन्तव्य स्थान में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो निर्यातकर्ता सम्पूर्ण या आंशिक उत्पादों के लिए नये उद्भव-प्रमाण-पत्र जारी करने लिए, लिखित रूप में जारी उद्भव-प्रमाण-पत्र को संलग्न करने हुए आवेदन करेगा।

7. प्रदर्शनी के लिए आयात.—(i) प्रदर्शनी के लिये आयातित और प्रदर्शनी के दौरान अथवा उसके बाद बेच दिये गये उत्पाद पर एपटा प्रदत्त वरीयता टैरिफ संव्यवहार का लाभ मिलेगा बशर्ते कि ऐसा उत्पाद उक्त नियमावली की शर्तों को पूरा करता हो और बशर्ते कि भारत का संबंधित सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि :—

(क) निर्यातकर्ता ने उन उत्पादों को निर्यात करने वाले सहभागी राज्य के भू-क्षेत्र से भारत को भेजा है जहां कि प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और इसका प्रदर्शन भी किया गया है।

(ख) निर्यातकर्ता ने माल को भारत के परेडिती को बेचा है या उसका अंतरण किया है; और,

(ग) उत्पाद प्रदर्शनी के दौरान अथवा उसके तत्काल बाद उसी राज्य में बेचा गया है जहाँ प्रदर्शनी के लिए भेजा गया है।

(ii) उपर्युक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये, उद्भव-प्रमाण-पत्र भारत में संबंधित सीमा-शुल्क प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(iii) उन-पैराग्राफ(i) प्रदर्शनियों, मेले और इसी प्रकार के आयोजनों के लिए तब लागू होगा जब उत्पाद घटना के दौरान सीमा शुल्क के नियंत्रण में हो।

8. उद्भव एवं अन्य प्रशासनिक मामलों के अभिप्रमाणन एवं सत्यापन से संबंधित प्रचालन प्रक्रिया.—एपटा के अंतर्गत उद्भव और अन्य सहमति प्राप्त मुद्दों के अभिप्रमाणन और सत्यापन के लिये प्रचालन प्रक्रिया एपटा के अंतर्गत उक्त नियमावली के क्रियान्वयन के मामले में लागू होगी, जिसमें निम्नलिखित मामले भी शामिल होंगे यथा :—

(क) जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, पता और सरकारी मुहर नमूना और हस्ताक्षर के बारे में जानकारी का सम्प्रेषण।

(ख) उद्भव-प्रमाण-पत्र, को जारी करने के लिए आवेदन का तरीका करने का और जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

(ग) जारी करने वाले अधिकारी के दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता।

(घ) किसी धोखधड़ी के मामले में अथवा माल के उद्भव, वर्गीकरण आदि के निर्धारण में और अन्य मामलों से संबंधित कोई विवाद पैदा हो जाता है तो एपटा भागीदार राज्यों का सहयोग।”

[फा. सं. 467/63/2006-सीमा-शुल्क-V]

सतीश कुमार रेडडी, निदेशक

नोट:— प्रधान नियमावली को का.आ.1390 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

### NOTIFICATION

New Delhi the 9th July, 2009

No. 79/2009-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 1679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following amendment in the Rules of Determination of Origin of Goods under the Asia-Pacific Trade Agreement (formerly known as the Bangkok Agreement) Rules, 2006, namely :—

In the said rules, —

(a) for rule 8, the following rule shall be substituted namely:—

“RULE 8. Certificate of origin.-Products eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin in the form specified in Annexure A and issued by an authority designated by the Government of the exporting Participating State and notified to the other Participating States, in accordance with the provisions specified in Annexure B.”

(b) after Annexure A, the following Annexure shall be inserted, namely:—

### “ANNEXURE-B

#### Procedure Regarding Claim of Preferential Concessions and Certificate of Origin of Goods under the Asia-Pacific Trade Agreement

The following provisions shall be complied with for preferential concessions under the Asia-Pacific Trade Agreement (hereinafter referred to as “APTA”):—

1. Issuing Authorities.—An authority or authorities designated by the Government of the exporting APT A Participating State (hereinafter referred to as “Issuing Authority”) shall issue the Certificates of Origin.

2. Certificate of Origin.—(1) The Certificates of Origin.—

- (a) shall be on an ISO A4 size paper in conformity with the specimen text set out in Annexure A, which shall be printed in English.
- (b) shall bear a unique reference number separately given by each place of office of issuance.
- (c) shall be issued manually or electronically by the Issuing Authority of the exporting APTA Participating State at the time of exportation or within three working days from the date of shipment.
- (d) shall be valid for one year from the date of issuance.
- (e) shall be without erasures and superimposition and unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition.
- (f) shall have the relevant rules and applicable percentage of regional content in Box 8.

(2) In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin, a certified true copy of the original, issued by the Issuing Authority, bearing the words "Certified True Copy" in Box 3, and the date of issuance of the original Certificate of Origin, shall be accepted and the certified true copy of a Certificate of Origin shall be issued within the validity period of the original Certificate of Origin.

**3. Presentation of the Certificate of Origin.—**(i) An original Certificate of Origin shall be submitted for preferential treatment to the Customs authority at the time of lodging the import entry for the products concerned.

(ii) The Certificate of Origin shall be submitted to the Customs authority at the port or place of importation within its validity period.

(iii) Where a Certificate of Origin is submitted to the relevant Customs authority at the port or place of importation after the expiration of its validity, such Certificate is still to be accepted when failure to observe the time limit results from *force majeure* or other valid causes beyond the control of the exporter.

(iv) In all cases, the relevant Customs authority may accept such Certificate of Origin provided that the products were imported before the expiration of the validity of the Certificate of Origin.

(v) Where the origin of a product is not in doubt, the discovery of minor discrepancies between the statements made in the Certificate of Origin and those made in the documents submitted to the Customs authority at the port or place of importation for the purpose of carrying out the formalities for importing the

products shall not *ipso-facto* invalidate the Certificate of Origin, if it does in fact correspond to the said products.

**4. Supporting documents of direct transportation .—**Under sub-rule (b) of rule 6 of the said rules, where the goods are transported through the territory outside the APTA Participating States, the following documents shall be presented to the Customs authorities at the port of import, namely:—

- (a) the through Bill of Lading issued in the exporting APTA Participating State;
- (b) the Certificate of Origin issued by the Issuing Authority of the exporting APTA Participating State;
- (c) the original commercial invoice in respect of the goods; and
- (d) supporting documents which prove the compliance with sub-rule (b) of rule 6 of the said rules.

**5. Origin verification.—**(i) The Customs authority may request the Issuing Authority of the exporting APTA Participating State for a retroactive random check and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the documents or as to the accuracy of the origin status of the goods in question.

(ii) The request shall be accompanied by the Certificate of Origin concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin may be inaccurate.

(iii) The Customs authority may suspend the preferential treatment while awaiting the result of the verification:

Provided that it may release the goods to the importer subject to any administrative measures deemed necessary :

Provided further that the goods are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.

(iv) (a) The Issuing Authority receiving a request for verification shall respond to the request promptly and reply within three months after receipt of the request.

(b) The verification process, including the actual process and the determination of whether the subject goods are originating or not, should be completed and the result should be communicated to the Issuing Authority within six months.

(c) While the process of the verification is being undertaken, the provisions of sub-paragraph (iii) shall be applied.

(v) In the cases where the Customs authority in India does not receive any reply within four months after the making of the request, the Customs authority may deny the claim for preferential treatment and in case the reply does not supply enough information to confirm the authenticity of the documents or the origin of the goods, the concerned authorities shall resolve the issue through bilateral consultation within three months, failing which the preferential treatment may be denied.

**6. Change in destination.**—The following procedures shall be complied with when the destination of all or parts of the products exported to a specified port is changed, before or after their arrival in India, namely :—

- (a) If the products have already been submitted to the Customs authority in India, the Certificate of Origin shall, following a written application by the importer, be endorsed to this effect for all or parts of products by the said authorities and the original returned to the importer.
- (b) If the change of destination occurs during transportation to India as specified in the Certificate of Origin, the exporter shall apply in writing, accompanied by the issued Certificate of Origin, for the issuance of new Certificate of Origin for all or parts of products.

**7. Imports for exhibition.**—(i) Products imported for exhibition and sold during or after the exhibition shall benefit from the preferential tariff treatment provided in the APTA, on the condition that the products meet the requirements of the said rules and provided it is shown to the satisfaction of the relevant customs authorities in India that :—

- (a) the exporter has dispatched those products from the territory of the exporting Participating State to India where the exhibition is held and has exhibited them there;

- (b) the exporter has sold the goods or transferred them to a consignee in India; and
- (c) the products have been sold during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for the exhibition.

(ii) For the purposes of implementing the above provisions, the Certificate of Origin must be produced to the relevant customs authorities in India.

(iii) The sub-paragraph (i) shall apply to exhibitions, fairs or similar shows or displays where the products remain under Customs control during the events.

**8. Operational procedures for the certification and verification of origin and other related administrative matters.**—The operational procedures for the certification and verification of origin and other related administrative matters agreed under APTA shall be applicable for implementing the said rules under APTA including the following matters, namely:

- (a) Communication of names, addresses and specimen official seals and signatures of the Issuing Authority.
- (b) Manner of application for issuance of Certificate of Origin and procedure to be followed by the Issuing Authority.
- (c) Requirement of keeping the records by the Issuing Authority.
- (d) Cooperation of the APTA Participating States in case of fraudulent acts and disputes concerning origin determination, classification, goods or other matters."

[F. No. 467/63/2006-Cus.V]

SATISH KUMAR REDDY, Director

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S. O. 1390 (E), dated the 31st August, 2006.

251348109-2